ग्रामीण भारत के वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों पर एक अध्ययन

[1]राजशेखर सिंह

[1]शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, मलिकपुरा डिग्री कॉलेज,गाजीपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर

सार

दृष्टि:

ग्रामीण वित्तीय स्थिति का गहराई से अध्ययन करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों क्या वित्तीय समस्याएं हैं एवं उनको दूर करने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं

अध्ययन का उद्देश्य:

प्रस्तावित शोध विषय का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को समझना है, विशेष रूप से उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता। हम उपयुक्त, व्यवहार्य और व्यावहारिक समाधान के साथ आने का इरादा रखते हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

योजना:

हमारा लक्ष्य पहले ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त के स्रोतों को समझकर यह शोध करना है। इनमें बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्रामीण आबादी के लिए उपलब्ध अन्य स्रोत शामिल हैं।

मुख्य शब्द: वित्तीय क्षेत्र, गैर-वित्तीय क्षेत्र, ग्रामीण भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था

परिचय

भारत देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के समग्र विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय राज्य एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र समग्र आर्थिक विकास की रीढ़ है। देश की अधिकांश आबादी में ग्रामीण आबादी शामिल है, जो कुल आबादी का

कुल 65% है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं राष्ट्र के समग्र विकास और विकास में एक अनिवार्य भूमिका निभाती हैं।

भारतीय वित्तीय प्रणाली मोटे तौर पर 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित है; अर्थात् संगठित और असंगठित वित्तीय क्षेत्र। जबकि संगठित वित्तीय क्षेत्र में बैंक, पूंजी बाजार और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं। दूसरी ओर, असंगठित क्षेत्र में कम नियंत्रित वित्तपोषक जैसे साहूकार, साहूकार, क्षेत्रीय और स्वदेशी बैंकर शामिल हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर असंगठित वित्तीय क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

ग्रामीण और कृषि क्षेत्र वित्तीय संस्थानों से पूरी तरह से लाभान्वित नहीं होते हैं, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मुकाबले वाणिज्यिक और संगठित बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच एक अतिरंजित अंतर मौजूद है। इससे ग्रामीण जनसांख्यिकी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है क्योंकि वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। साहूकार उनसे उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंकों को कम ब्याज दर वसूलने का निर्देश दिया गया था।

साहित्य की समीक्षा

एमडी शाहनवाज अब्दीन, राहुल कुमार (2020) भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से दूर किए जाने वाले समग्र योगदान, उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों की समीक्षा करते हैं, जो भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्षों के अनुसार, कृषि क्षेत्र की वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद के बीच एक पाया गया सहसंबंध है और इस प्रकार यह भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति होगी। यह पत्र भारत सरकार को किसानों के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियां बनाकर कृषि बाजारों में सुधार करने में मदद करने और गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सिफारिश करता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों को उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की ओर विविधता लाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

डॉ. डी. जेबसेल्वी अनीता (2020) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की गई विभिन्न वित्तीय पहलों का अध्ययन करती है। यह पाया गया कि नाबार्ड ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अपनी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास की पहल के माध्यम से योगदान दिया है. नाबार्ड संस्था के वित्त पोषण और बैंकों के विनियमन की निगरानी करने में सफल रहा है। इन पहलों से कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों में विकास के

माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की आपात स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर प्रासंगिकता रखती है। अध्ययन इस तथ्य पर जोर देता है कि नाबार्ड किसी भी प्रकार की बाधाओं से जूझकर ग्रामीण विकास में मदद करेगा.

विकास रावल एट अल (2020) ने भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन और परीक्षण किया। द्वितीयक आंकड़ों को सूचना के स्रोत के रूप में एकत्र किया गया था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उपलब्ध आंकड़ों को इस अध्ययन की कार्यप्रणाली के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। किए गए शोध के अनुसार, COVID-19 के कारण लॉकडाउन के कारण हुए कुछ व्यवधानों में फसल का नुकसान, बढ़ा हुआ कर्ज का बोझ, किसानों की अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेचने में असमर्थता और किसानों के लिए आर्थिक बोझ में समग्र वृद्धि शामिल है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सरकार इस स्थिति का उपयोग किसानों और ग्रामीण श्रमिकों को राहत प्रदान करने के बजाय मेहनतकश लोगों के अधिकारों और संसाधनों के और अधिक निपटान के लिए एक अवसर के रूप में कर रही है।

जाना, डी., सिन्हा, ए., और गुप्ता, ए. (2019) भारतीय परिदृश्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। पेपर का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय सेवाओं के उपयोग और वित्तीय साक्षरता पर प्रभाव पर जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक चर के प्रभावों का पता लगाना था। अध्ययन में प्रयुक्त पद्धति प्राथमिक डेटा संग्रह है, जहां असंगठित क्षेत्र में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के श्रमिकों से डेटा एकत्र किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि व्यवसाय, आय, शिक्षा योग्यता और वैवाहिक स्थिति का भारत के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के वित्तीय साक्षरता स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंत में, वे सरकार को कमजोर वर्ग के शिक्षा स्तर में सुधार करने की सलाह देते हैं।

डॉ. प्रकाश जी. पटेल (2019) भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास और विकास में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका का अध्ययन करते हैं। अध्ययन ने निर्धारित किया है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि विकास ने समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कैसे प्रभावित किया है। वर्ष 2017-2018 में कृषि विकास दर 3.4% थी और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.7% थी। आईएमएफ ने 2018 के लिए 3.9% की वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया था। यह अध्ययन विभिन्न सुधारों और उपायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को निर्धारित करता है। इसके पीछे मकसद 2025 तक अर्थव्यवस्था को 5 अरब डॉलर और 2030 तक करीब 10 अरब डॉलर बढ़ाना है।

जाना, डी. (2018) ने भारत के पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के असंगठित क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विश्लेषण किया। मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के साथ वित्तीय साक्षरता के स्तर के साथ-साथ विभिन्न जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों के बीच किसी भी प्रभाव और संबंध की पहचान करना है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और बैंकिंग के बारे में अधिकांश ग्रामीण नागरिकों में जागरूकता कम है।

अमित बसोले (2017) बजटीय प्रावधानों का विश्लेषण करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या चाहिए। इस पत्र से, हम यह कह सकते हैं कि सरकार ग्रामीण रोजगार में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। आजीविका के विविधीकरण के माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण को प्राप्त करने के लिए सरकार को एक साहसिक दृष्टिकोण रखना होगा। ग्रामीण आय बढ़ाने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए बजट में दो अन्य पहलुओं पर ध्यान देने की सिफारिश की गई है। मनरेगा योजना का विस्तार लेखक द्वारा प्रस्तावित है।

रमेश चंद एट अल (2017) 1971 से 2012 तक भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास की प्रकृति और पिछले वर्षों में रोजगार सृजन के संदर्भ में व्यावसायिक संरचना पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। 2004-05 से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर-कृषि गतिविधियों के योगदान को ध्यान में रखा गया है। यह देखा गया है कि कृषि के हिस्से में कमी के बावजूद यह ग्रामीण भारत में रोजगार का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। साथ ही, यह भी पाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार में भारी असंतुलन है। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि गतिविधियों में स्थानांतरित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए जाने चाहिए।

टीना शिवानी (2017) भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए की गई सरकारी पहलों की समीक्षा इसके लाभों और चुनौतियों के संदर्भ में करती है। मूल्यांकन करता है कि क्या ये नीतियां ग्रामीण लोगों को जोड़ने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। यह अध्ययन उसी क्षेत्र के साहित्य की समीक्षा करता है। यह पाया गया है कि वर्तमान सरकार विभिन्न सामाजिक और वित्तीय उपशमन योजनाएं लेकर आई है, लेकिन वे बहुत सफल नहीं हैं। यह पत्र बताता है कि विमुद्रीकरण के बाद कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और ग्रामीण लोग

इन लाभों का उपयोग करने के बारे में अधिक जागरूक हैं। एक व्यापक प्रणाली की उपस्थिति से ग्रामीण आबादी को भी भारत के आर्थिक विकास का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

डॉ. एम. सैयद इब्राहिम (2016) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका का विश्लेषण करते हैं। आरआरबी की स्थापना के पीछे का उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण आबादी को ऋण प्रदान करना है। इस अध्ययन की प्रकृति निदानात्मक और खोजपूर्ण है और उपयोग की जाने वाली पद्धति द्वितीयक डेटा संग्रह है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में आरआरबी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का प्रतिशत अधिक होता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अल्पावधि और सावधि ऋणों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को ऋण दिया है। अर्थव्यवस्था पर गैर-कृषि क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव के साथ, अध्ययन से पता चलता है कि आरआरबी को उन्हें ऋण का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए।

साहू, एम.के. एट अल (2015) वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की उपलब्धता का अध्ययन करता है, अर्थात, गुजरात राज्य में असंगठित क्षेत्रों का वित्तीय समावेश, विशेष रूप से गांधीनगर जिले के कुछ हिस्सों में। पेपर का प्राथमिक उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्रों के निम्न-स्तरीय वित्तीय समावेशन का पता लगाना और जनसंख्या पिरामिड के निचले भाग में स्थित वित्तीय समावेशन में सुधार के तरीकों को लागू करना है। अध्ययन के निष्कर्षों का अर्थ है कि जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं थी, जनसंख्या के 25% ने अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लिया, और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की उपलब्धता प्रदान करते हुए महिलाओं के प्रति लैंगिक पक्षपात किया। अध्ययन में सरकार को वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

दिवाकर, एन., और अहमद, टी. (2014) भारत में असंगठित क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करता है। चुनौतियों को दूर करने के लिए, सरकार ने इन क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ नियमों, अधिनियमों, योजनाओं के साथ-साथ असंगठित क्षेत्रों में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है। असंगठित क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और साक्षरता एक बाधा बन गई है जो रहने की स्थिति के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए पेपर का मुख्य उद्देश्य सरकार को चुनौतियों को कम करने और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रदान की गई विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करने की सिफारिश करना है।

गनी, ई., केर, डब्ल्यू.आर., और ओ'कोनेल, एस.डी. (2013) असंगठित क्षेत्रों में भारत के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करता है, जो इसके विकास, आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन भारत के विनिर्माण और सेवाओं में असंगठित क्षेत्र के बारे में कई

महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में लाता है और कई स्थितियों की जांच करता है जो राज्यों द्वारा परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। असंगठित क्षेत्र के नियोजित श्रमिक भारत में उल्लेखनीय रूप से लगातार और बड़े हैं।

कुलश्रेष्ठ, ए.सी. (2011) असंगठित क्षेत्र की समस्याओं और भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए उपायों की जांच करता है। इस अध्ययन का आधार अनौपचारिक क्षेत्र के आकार को रोजगार सृजित करने के संदर्भ में मापना है। यह पाया गया है कि व्यापार, कृषि गतिविधियाँ, विनिर्माण और होटल और रेस्तरां अन्य दो आर्थिक गतिविधियाँ हैं जो अर्थव्यवस्था की असंगठित आय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

परवीन शर्मा (2011) भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। यह पेपर भारत के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण आबादी को आईटी-आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए चल रही विभिन्न पहलों पर जोर देता है। अध्ययनों से पता चलता है कि आईटी सेवाओं को मौजूदा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के संबंध में डिजाइन किया जाना चाहिए। शिक्षा या बाजार के अवसरों के संदर्भ में भारत की ग्रामीण आबादी के लिए समृद्ध जानकारी लाने की सिफारिश की गई है। यह भारतीय ग्रामीण आबादी की भौतिक भलाई पर सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने में मदद करेगा।

टी हक (1985) भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के क्षेत्रीय रुझानों और पैटर्न का अध्ययन करता है। इस अध्ययन के माध्यम से भारत के कई क्षेत्रों में ग्रामीण विविधीकरण की विभिन्न दीर्घकालिक संभावनाओं का निर्धारण किया गया है। इस अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न उपक्षेत्रों में कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के राज्य-वार डेटा का संग्रह शामिल है। इस अध्ययन के माध्यम से, हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आने वाले कई और वर्षों तक फसल आधारित बनी रहेगी। विश्लेषण से एक और अवलोकन यह है कि व्यवसाय की पाली में एक समान असर नहीं होता है। अंत में, इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि ग्रामीण गरीबी और विविधीकरण का भारत में सामान्य संबंध नहीं है।

वित्तीय समावेशन की मुख्य चुनौती

- ग्रामीण और गरीब लोगों को कवरेज क्षेत्र में शामिल करना है।
- वित्तीय निरक्षरता भी वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में चुनौतियों में से एक है। बुनियादी शिक्षा का अभाव लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने से रोकता है।

- ग्रामीण ऋण एजेंसियां और इसकी योजनाएं छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही हैं। इस प्रकार, जरूरतमंद किसानों की ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया गया है जबकि तुलनात्मक रूप से संपन्न किसानों को उनकी बेहतर ऋण योग्यता के लिए क्रेडिट एजेंसियों से अधिक ध्यान मिल रहा है।
- आज की वित्तीय सेवा कंपनियों को न केवल ग्राहकों को आकर्षित करना मुश्किल लगता है, बल्कि उन्हें कर्मचारियों को आकर्षित करना भी मुश्किल हो रहा है। नई आईटी भूमिकाओं को भरने के लिए योग्य प्रतिभा की कमी, और एक सहस्राब्दी कार्यबल जो दीर्घकालिक रोजगार को छोड़ देता है, अच्छी मदद पाने के प्रमुख कारक हैं
- भारत के बैंकों के सामने 5 प्रमुख चुनौतियाँ

(i) संपत्ति की गुणवत्ता: भारत के बैंकों के लिए सबसे बड़ा जोखिम खराब ऋणों में वृद्धि है।

(ii) पूंजी पर्याप्तता: एक तरह से बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वह खराब ऋणों से सुरक्षित रहे, धन को 'प्रावधान' के रूप में अलग रखा जाए।

(iii) अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर

(iv) कर्मचारी और प्रौद्योगिकी

(v) बैलेंस शीट प्रबंधन

(vi) भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या क्या है?

- ग्रामीण ऋण एजेंसियां और इसकी योजनाएं छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही हैं। इस प्रकार, जरूरतमंद किसानों की ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया गया है जबकि तुलनात्मक रूप से संपन्न किसानों को उनकी बेहतर ऋण योग्यता के लिए क्रेडिट एजेंसियों से अधिक ध्यान मिल रहा है।
- निहित लाभ के उद्देश्य के कारण यह चरित्र में अत्यधिक शोषक है। 2. चूंकि इस तरह के क्रेडिट बड़े पैमाने पर अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं, इसलिए ब्याज की दर बहुत अधिक है।
- जैसे-जैसे बैंक और वित्तीय सेवाएं ग्रामीण भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार करना जारी रखती हैं, वे आसपास के क्षेत्र में रोजगार पैदा कर रही हैं। • ग्रामीण वित्त विशेष रूप से कृषि उद्योग की आवश्यकताओं के लिए लक्षित ऋण की एक पंक्ति है।

- बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए ऋण, ऋण-स्थगन, और हस्तक्षेप योजनाओं को जारी रखते हुए अपने नुकसान को संतुलित करना है।
- साथ ही, सरकार इन संस्थानों का नियंत्रण प्राधिकारी भी है। चूंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली में संस्थानों की बहुलता है, इसलिए इन संस्थानों के कामकाज में समन्वय का अभाव है।
- साथ ही, सरकार इन संस्थानों का नियंत्रण प्राधिकारी भी है। चूंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली में संस्थानों की बहुलता है, इसलिए इन संस्थानों के कामकाज में समन्वय का अभाव है।

सुझाव

विश्वसनीयता ठीक करें

बीसी की विश्वसनीयता के मुद्दे को हल करने के लिए, बैंक डाकघरों और उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं और बैंक रहित आबादी के लिए बैंकिंग काउंटर प्रदान कर सकते हैं। ऑडियो-वीडियो सेवाओं वाले बहु-भाषा एटीएम पर भी विचार किया जा सकता है। अपनी ओर से, बैंक अपनी सुविधाओं/परिसरों के उपयोग के लिए भारतीय डाक और उचित मूल्य की दुकानों को 'किराया शुल्क' का भुगतान कर सकते हैं। कम कमीशन/आय के कारण उच्च एट्रिशन रेट को संबोधित करने के लिए, बैंक अपनी नियमित आय के पूरक के लिए बीसी बनने के लिए गृहिणियों, और उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों, सेवानिवृत्त लोगों और सीमित विकलांग लोगों को नामित करने पर विचार कर सकते हैं। बीसी के व्यवसाय में लोगों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए, बीसी के माध्यम से अधिक वित्तीय सेवाओं को रूट करके उच्च कमीशन के प्रावधान के साथ-साथ उन्हें सम्मानजनक पदनाम और पहचान पत्र प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, बोनस या पदोन्नति या अवशोषण के संदर्भ में प्रोत्साहन संरचित लाभ के साथ। मुख्यधारा की बैंकिंग।

विभिन्न वर्गों के अनुरूप विविध उत्पादों की पेशकश करें

भारत अद्वितीय क्षेत्रीय और व्यावसायिक विशेषताओं वाला एक विविध देश होने के नाते, और विभिन्न फसल पैटर्न और आय धाराओं का पालन करते हुए, इसकी असंबद्ध आबादी के लिए विविध उत्पादों का होना आवश्यक है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग योजनाओं, अधिमानतः विभिन्न योजनाओं की आवश्यकता है। इसके अलावा, लोगों के रोजगार की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, दिहाड़ी मजदूरों को दैनिक आधार पर छोटे-छोटे जमा करने की अनुमति दी जा सकती है।

स्थानीय निकायों की भूमिका

अंत में, 100 प्रतिशत सफलता प्राप्त करने के लिए, गांवों और शहरों दोनों में स्थानीय सरकारों से मदद लेने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं और नगर परिषदें न केवल पहचान करने में मदद कर सकती हैं बल्कि औपचारिक बैंकिंग चैनलों में परिचालन शुरू करने के लिए गैर-बैंकिंग को प्रोत्साहित कर सकती हैं। भारी जनादेश और नई आशा के साथ नई सरकार इसे हासिल कर सकती है और दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए मेड इन इंडिया की एक धधकती सफलता की कहानी स्थापित कर सकती है।

संदर्भ

[1] अबदीन, डी.एम.एस., और कुमार, आर. भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर रही है: योगदान, अवसर और चुनौतियां।

[2] अनीता, जे. (2020)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा की गई वित्तीय पहल पर एक अध्ययन। SSRN 3531601 पर उपलब्ध है।

[3] बसोल, ए (2017)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या चाहिए? आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 52(9), 40-43।

[4] चांद, आर., श्रीवास्तव, एस.के., और सिंह, जे. (2017)। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, 1971 से 2012 तक। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 52(52), 64-71।

[5] दिवाकर, एन., और अहमद, टी. (2014)। असंगठित क्षेत्रों के सामने आने वाली समस्याएं और चुनौतियाँ: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य। न्यू मैन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज, 1, 12-31।

[6] गनी, ई., केर, डब्ल्यू.आर., और ओ'कोनेल, एस.डी. (2013)। भारत के असंगठित क्षेत्र की असाधारण दृढ़ता। विश्व बैंक।

[7] हक, टी. (1985)। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के क्षेत्रीय रुझान और पैटर्न। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 40(902-2018-2393), 291-297।

[8] इब्राहिम, एम. एस. (2016)। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका-एक विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ कंप्यूटर साइंस, 2(1).

[9] जाना, डी. (2018)। पश्चिम बंगाल (भारत) के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का एक तुलनात्मक अध्ययन: असंगठित क्षेत्र से साक्ष्य। राजगिरी मैनेजमेंट जर्नल, 12(1), 5-22.

[10] जाना, डी., सिन्हा, ए., और गुप्ता, ए. (2019)। वित्तीय साक्षरता और वित्तीय सेवाओं के उपयोग के निर्धारक: भारतीय परिदृश्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच एक अनुभवजन्य अध्ययन। प्रबंधन अध्ययन के ईरानी जर्नल, 12(4), 657-675।

[11] कुलश्रेष्ठ, ए.सी. (2011)। भारत में असंगठित क्षेत्र का मापन। आय और धन की समीक्षा, 57, S123-S134।

[12] पटेल, डी.पी.जी. (2019)। भविष्य के विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका का अध्ययन। जर्नल ऑफ़ द गुजरात रिसर्च सोसाइटी, 21(1), 238-250.

[13] रावल, वी., कुमार, एम., वर्मा, ए., और पेस, जे. (2020)। COVID-19 लॉकडाउन: कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक अनुसंधान के लिए सोसायटी।

[14] साहू, एम.के. (2015)। भारत में वित्तीय समावेशन: गुजरात में असंगठित क्षेत्र का एक अनुभवजन्य अध्ययन। सूचना प्रबंधन और व्यापार समीक्षा, 7(5), 6-17।

[15] शर्मा, पी. (2011)। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 4(1), 187-190।